

## डीप ओशन मशिन

### प्रलिमिंस के लयि:

डीप ओशन मशिन, ब्लू इकॉनमी, मानवयुक्त सबमर्सबिल वहीकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ।

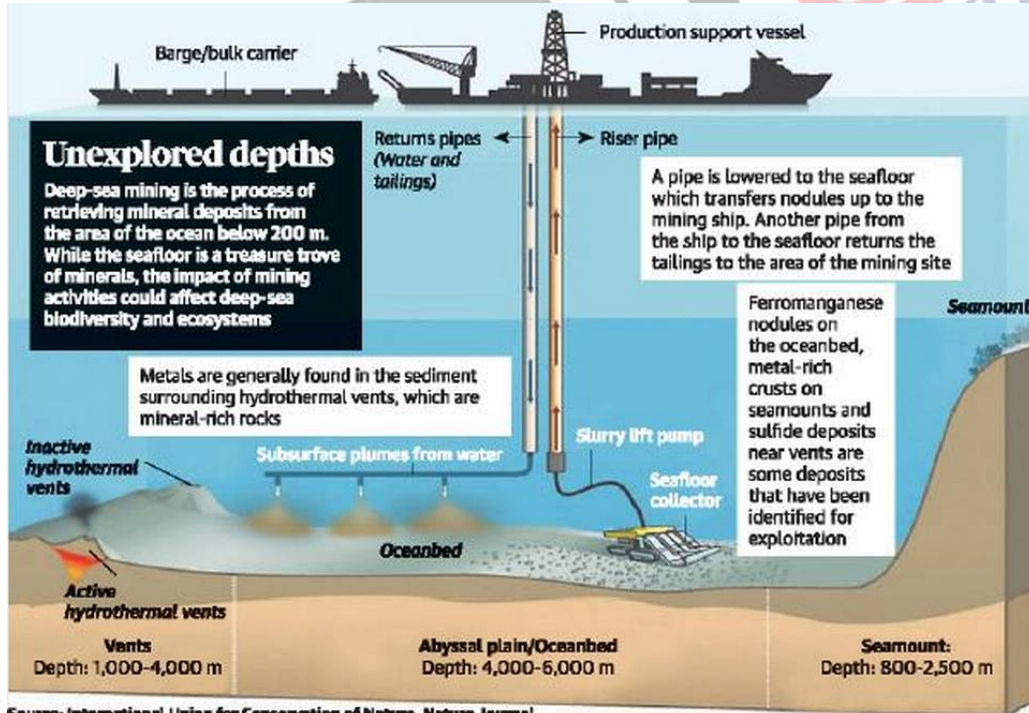
### मेन्स के लयि:

डीप ओशन मशिन, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, वैज्ञानिक नवाचार और खोजें, ब्लू इकॉनमी ।

### चर्चा में क्यौं?

हाल ही में पृथ्वी वज्जान मंत्रालय द्वारा **डीप ओशन मशिन** (Deep Ocean Mission- DOM) लॉन्च कयिा गया है ।

- DOM भारत सरकार की ब्लू इकॉनमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मशिन मोड प्रोजेक्ट है ।
- इससे पूरव पृथ्वी वज्जान मंत्रालय ने **ब्लू इकॉनमी** पॉलिसी का मसौदा भी तैयार कयिा गया था ।
- ब्लू इकॉनमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोज़गार एवं स्वस्थ महासागर पारस्थितिकी तंत्र के लयि समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है ।



// Source: International Union for Conservation of Nature, Nature Journal

### प्रमुख बडि

### DOM के प्रमुख घटक:

- मानवयुक्त सबमर्सबिल वाहन का विकास:

- तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिये वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी।
- NIOT और इसरो संयुक्त रूप से एक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन/पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- गहरे समुद्र में खनन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास:
  - मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस के खनन के लिये एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
    - पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस समुद्र तल में मौजूद लोहे, मैंगनीज़, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें हैं।
  - भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संगठन 'इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी' द्वारा जब भी वाणिज्यिक खनन कोड तैयार किया जाएगा ऐसी स्थिति में खननों के अन्वेषण अध्ययन से निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा।
- महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास:
  - इसके तहत जलवायु परिवर्तनों के भविष्यगत अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं मॉडलों के एक समूह का विकास किया जाएगा।
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिये तकनीकी नवाचार:
  - इसके तहत सूक्ष्मजीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों के सर्वेक्षण एवं गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण:
  - इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनन के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है।
- महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी:
  - इसमें अपतटीय 'महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण' (OTEC) वलिवणीकरण संयंत्र हेतु अध्ययन और वसितृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना शामिल है।
  - OTEC एक ऐसी तकनीक है, जो ऊर्जा दोहन के लिये सतह से समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है।
- महासागर जीवविज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन:
  - इस घटक का उद्देश्य महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता एवं उद्यम का विकास करना है।
  - यह घटक ऑन-साइट बजिनेस इन्क्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा।

## 'डीप ओशन मशिन' का महत्त्व:

- महासागरीय संसाधनों का लाभ उठाना: महासागर विश्व के 70% हस्सिसे को कवर करते हैं और हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हस्सिसे हैं। महासागरों की गहराई में स्थिति लगभग 95 प्रतिशत हस्सिसे ऐसा है जिसका अब तक अन्वेषण नहीं किया जा सका है।
  - भारत तीन दशाओं से महासागरों से घिरा हुआ है और देश की लगभग 30 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है, साथ ही महासागर मत्स्यपालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका एवं 'ब्लू इकॉनमी' का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
  - संवहनीयता पर महासागरों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान के दशक (Decade of Ocean Science for Sustainable Development) के रूप में घोषित किया है।
- लंबी तटरेखा: भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा में नौ तटीय राज्य और 1,382 द्वीप हैं।
  - फरवरी 2019 में प्रतिपादित किये गए भारत सरकार के 2030 तक के नए भारत के विकास की अवधारणा (India's Vision of New India by 2030) के दस प्रमुख आयामों में से ब्लू इकॉनमी भी एक प्रमुख आयाम है।
- तकनीकी विशेषज्ञता: ऐसे मशिनों के लिये आवश्यक तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में केवल पाँच देशों- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास उपलब्ध है।
  - भारत ऐसी तकनीक वाला छठा देश होगा।

## नीली अर्थव्यवस्था/ब्लू इकॉनमी से संबंधित अन्य पहलें:

- सतत् विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स:
  - भारत और नॉर्वे के बीच ब्लू इकॉनमी को लेकर संयुक्त पहल विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
- सागरमाला परियोजना:
  - सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिये आईटी-सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह के विकास हेतु रणनीतिक पहल है।
- ओ-स्मार्ट (O-SMART):
  - ओ-स्मार्ट एक अम्बरेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का वनियमित उपयोग करना है।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र परबंधन:
  - यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति:
  - भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर 'ब्लू ग्रोथ इनशिएटिव' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है।

## वर्गित वर्षों के प्रश्न

प्र. यदरशरुद्रीय जल मशरन को सही ढंग से और पूरणतः लागू कयल जाए तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (2012)

- 1- शहरी कषेत्रों की जल आवशकताओं की आंशकल आपूरतअपशषलट जल के पुनरुचकरण से हो सकेगी ।
- 2- ऐसे समुदरतटीय शहर-जनलके पास जल के अपरुयापूत वैकलपकल सुरुत हैं, की जल आवशुयकताओं की आपूरतऐसी समुचतल पौदुयोगकी वुयवहार में लाकर की जा सकेगी, जो समुदरी जल को प्रुयोग लायक बना सकेगी ।
- 3- हमललय से उदुगमतल सभी नदरुयलँ प्रुयादुवीपीय भारत की नदरुयलँ से जोड़ दी जांंगी ।
- 4- सरकार कृषकों दुवारा भौम जल नकललने के लयल बोरगल से खोदे गए कुँ और उन पर लगाई गई मोटर तथा पम्प-सेट पर वहन कयल वुयव की पूरी तरह प्रतपूरतकरेगी ।

नीचे दयल गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनयल:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

सुरुतः पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/deep-ocean-mission-2>

